श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं श्रीमती मोहसिना किदवई के ज़ीरो आवर मेंशन से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

Demand to amend the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 to save demolition of houses of fishermen

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, on account of the Coastal Regulation Zone Notification, 1991, about 8,000 houses on the sea coast of Goa are facing demolition. Sir, the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 came into force with effect from 19th February, 1991. The Panaji Bench of Bombay High Court has given certain directions to the Revenue authorities for supervising 105 kms. of Goa coastline and has directed them to demolish constructions, built prior to 1991 and in the post 1991 period, in violation of CRZ regulations and plans.

On 26th September, 2007, the Panaji Bench has issued directions to Panchayats and municipal bodies in Goa to identify all such structures existing as on 1991 and take action against all other structurers/extensions carried out without permission in accordance with the law.

There are about 4,553 structures which have come up post 1991 on Goa coast, within 200 to 500 mtrs., and 2,272 structures, within 100 mtrs.

Sir, most of these houses are occupied by fisher folk communities. Members of fisher folk communities keep their fishing implements, motor and motor equipments, fishing implements, fishing nets etc., in these houses.

Taking the circumstances into consideration, a way has to be found out to save these structures which may be considered as violative of CRZ regulations.

The only remedy to do this is to carry a Goa specific amendment to the CRZ III(i) to protect constructions as existing up to 1.1.2007 within the 'No Development Zone', *i.e.* from o to 200, and, then, to permit the existing limit of constructions from two times the number to four times the number of dwelling units under CRZ III(iii).

People of Goa are strongly agitated over the issue as the axe is likely to fall on about 8,000 houses on the coastal belt of Goa. Any law which does not recognize human sentiments is no law.

Ill-treatment meted out to students from other States during an examination of Railway Recruitment Board in Mysore

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : सर, मैं आपके माध्यम से एक अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे हिन्दुस्तान में संघीय व्यवस्था है। उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी आदमी कहीं भी रोजगार कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और कोई भी application for employment दे सकता है। सर, महाराष्ट्र में इसकी शुरूआत हुई। असम में तो यह पहले से चल रहा है। हमारे गरीब लोग असम में मजदूरी करने जाते हैं। वहां उनको गोली से मार दिया जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। कई बार सरकार ने आश्वासन दिया कि हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

दूसरी बात यह है कि हमारे पढ़े-लिखे बच्चे परीक्षा देने दूर-दूर तक जाते हैं। वे महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं या जहां कहीं भी एम्प्लायमेंट होती है, वहां वे नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं। लेकिन, पता नहीं वहां क्या

होता है कि वहां जो बिहारी लोग जाते हैं, उनको चुन-चुन कर उनसे यह पूछा जाता है कि आप कहां से आये हो, आपकी शक्ल तो बिहारी की तरह लगती है? सर, शक्ल तो इंसान नही बनाता बल्कि भगवान बनाता है। उनसे यह सब पूछ कर उनको टार्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, Examination Hall में घुसकर उनके पर्चे छीन लिये जाते हैं। सर, यह बहुत गंभीर मामला है। इसके बारे में अगर आप लोग कोई विचार नही करेंगे तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वह आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आदमी सिकुड़ कर अपने ही राज्य में रह जाएगा, कोई बाहर नही जा पाएगा। इसलिए मेरी राय यह है कि अगर कोई केन्द्रीय परीक्षा होती है, जैसे अगर रेलवे की कोई केन्द्रीय परीक्षा हो तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि या तो जो लोग बाहर से परीक्षा देने कही जाते हैं तो वहां उनकी पूरी सुरक्षा हो अथवा ऐसी परीक्षाएं लोकल स्तर पर ही आयोजित होनी चाहिए। अगर ऐसा नही होगा तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे। सर, उनको वहां जाने में कितनी कठिनाई होती है! उपसभापति महोदय, यह आपके इलाके कर्नाटक की ही बात है।

श्री उपसभापति : नही, मुझे नही बताइये।

श्री राजनीति प्रसाद : वहां आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक में जो घटना हुई है, उस पर सरकार को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। सर, वहां यह घटना हुई कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : घटना बताने के लिए अब वक्त नही है।

श्री राजनीति प्रसाद : क्या मेरा समय खत्म हो गया? ...(**व्यवधान**)... सर, वहां Examination Hall के अंदर घुसकर उनकी कॉपी छीनकर उनको मारा गया। यह आपके इलाके का मामला है। इसकी इन्क्वायरी कराने की कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rama Jois. ...*(Interruptions)*....

SHRI SHANTARAM LAXMAN (Goa) : Sir, the Minister is here. Let him respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. It is not possible. ...*(Interruptions)*... It is not possible. Shri Rama Jois. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: He wants to respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: To what? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: To my submission. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. I am not allowing him. During Zero Hour no statement is made. Your Zero Hour mention is over. I have called the next hon. Member. Now I can't go back.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (Rajasthan): If the Minister concerned voluntarily comes, you can't stop.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Immediately after the Zero Hour, if the Minister had volunteered, I would have permitted him. When I have gone to some other subject, it is not correct. ...*(Interruptions)*... No. Let us not waste time. ...*(Interruptions)*... It is not advisable for the Minister also.

Firing of rockets by Pakistan in the villages of Punjab

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am inviting the attention of the House to a matter of serious concern for the security of the nation.